

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-*35

बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

रोजगार छिनने के संबंध में सीएमआईई प्रतिवेदन

*35. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी" (सीएमआईई) के हाल के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2018 में 11 मिलियन व्यक्तियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) जनवरी, 2019 के दौरान छिनी नौकरियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) उपरोक्त प्रतिवेदन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या वर्ष 2018 में 3.7 मिलियन वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (छ) इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा रोजगार छिनने के संबंध में सीएमआईई प्रतिवेदन के बारे में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *35 के भाग (क) से (छ) में दिनांक 06.02.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से छ): सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तथा सरकार को उनके द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2015 -16 में रोजगार-बेरोजगारी पर श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित बेरोजगारी दर एवं श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्रमशः 3.7% एवं 50.5% थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 28.01.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1,29,916 प्रतिष्ठान एवं 1.05 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

राज्य सभा के दिनांक 06.02.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *35 के भाग (क से छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2015-16 में सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दर एवं श्रमिक जनसंख्या अनुपात का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	बेरोजगारी दर (% में)	श्रमिक जनसंख्या अनुपात (% में)
1	आंध्र प्रदेश	3.5	61.6
2	अरुणाचल प्रदेश	3.9	62.1
3	असम	4.0	50.6
4	बिहार	4.4	48.4
5	छत्तीसगढ़	1.2	67.3
6	दिल्ली	3.1	40.8
7	गोवा	9.0	44.7
8	गुजरात	0.6	49.0
9	हरियाणा	3.3	44.7
10	हिमाचल प्रदेश	10.2	40.8
11	जम्मू एवं कश्मीर	6.6	36.7
12	झारखंड	2.2	65.2
13	कर्नाटक	1.4	55.5
14	केरल	10.6	45.2
15	मध्य प्रदेश	3.0	44.8
16	महाराष्ट्र	1.5	52.2
17	मणिपुर	3.4	59.9
18	मेघालय	4.0	62.8
19	मिजोरम	1.5	67.4
20	नागालैंड	5.6	63.5
21	ओडिशा	3.8	51.2
22	पंजाब	5.8	40.2
23	राजस्थान	2.5	53.7
24	सिक्किम	8.9	61.4
25	तमिलनाडु	3.8	56.3
26	तेलंगाना	2.7	56.6
27	त्रिपुरा	10.0	61.9
28	उत्तराखंड	6.1	44.6
29	उत्तर प्रदेश	5.8	43.7
30	पश्चिम बंगाल	3.6	50.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.0	54.1
32	चंडीगढ़	3.4	37.1
33	दादरा एवं नगर हवेली	2.7	45.4
34	दमन एवं दीव	0.3	50.1
35	लक्षद्वीप	4.3	34.6
36	पुडुचेरी	4.8	50.9
	अखिल भारत	3.7	50.5

स्रोत: श्रम ब्यूरो का रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण